



13 July, 2024

गैर-सब्सिडी वाले उर्वरक

संदर्भ: आगामी केंद्रीय बजट में उर्वरक क्षेत्र के लिए प्रमुख सुधार घोषणाओं की कमी होने की उम्मीद है, विशेष रूप से गैर-सब्सिडी वाले उर्वरकों के संबंध में।

➤ गैर-सब्सिडी वाले उर्वरकों पर नियंत्रण:

- एनबीएस (पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी) उत्पादों जैसे गैर-सब्सिडी वाले उर्वरकों को उनके पोषक तत्व (एन, पी, के, एस) के आधार पर प्रति टन सब्सिडी मिलती है।
- हाल ही में, इन उत्पादों पर अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण भी लगाए गए हैं, जहां लागत पर अधिकतम लाभ मार्जिन "उचित" अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निर्धारित किया जाता है।
- अप्रैल 2023 से प्रभावी, निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत लेने वाली उर्वरक कंपनियों को एनबीएस के तहत सब्सिडी खोने का जोखिम है।

➤ निर्धारित एमआरपी:

- अभी तक निर्धारित "उचित" एमआरपी डीएपी के लिए 27,000 रुपये प्रति टन, एमओपी के लिए 30,000-31,000 रुपये और एसएसपी के लिए 11,000 रुपये हैं।
- 20:20:0:13 जैसे जटिल उर्वरकों की कीमत 24,000 रुपये है, और 10:26:26:0 और 12:32:16:0 एनपीकेएस जैसे उर्वरकों की कीमत 29,400 रुपये है।

➤ बिक्री और बाजार की गतिशीलता:

- हाल के वर्षों (2022-23 और 2023-24) में उर्वरकों की बिक्री का लगभग 94% हिस्सा केवल सात उत्पादों से संबंधित था, जिसमें यूरिया, डीएपी, एसएसपी और चयनित एनपीकेएस उर्वरक शामिल हैं।
- नई राजनीतिक गतिशीलता के बावजूद, सरकार पर सीधे एमआरपी बढ़ाने के लिए बहुत कम राजकोषीय दबाव है।

➤ उर्वरक सब्सिडी के बारे में:

- सरकार उर्वरक उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान करती है ताकि किसान बाजार दरों से कम कीमत पर उर्वरक खरीद सकें।
- यह सब्सिडी उर्वरकों के उत्पादन या आयात की लागत और किसानों द्वारा भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर को कवर करती है।

➤ यूरिया पर सब्सिडी:

- यूरिया भारत का सबसे अधिक उत्पादित, आयातित, उपभोग किया जाने वाला और विनियमित उर्वरक है, जिसे विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए सब्सिडी दी जाती है।
- यूरिया पर सब्सिडी प्रत्येक विनिर्माण संयंत्र में उत्पादन लागत पर आधारित है, और इसे किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जाना चाहिए।
- यूरिया के लिए वर्तमान एमआरपी 5,628 रुपये प्रति टन तय की गई है।

➤ गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी:

- गैर-यूरिया उर्वरकों की एमआरपी विनिर्माताओं द्वारा नियंत्रण मुक्त या निर्धारित की जाती है।
- हालांकि, रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद हाल ही में वैश्विक मूल्य वृद्धि के कारण, इन उर्वरकों को सरकारी मूल्य नियंत्रण उपायों के अधीन किया गया है।
- सभी गैर-यूरिया उर्वरक पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के अंतर्गत आते हैं।

➤ वित्तीय विचार:

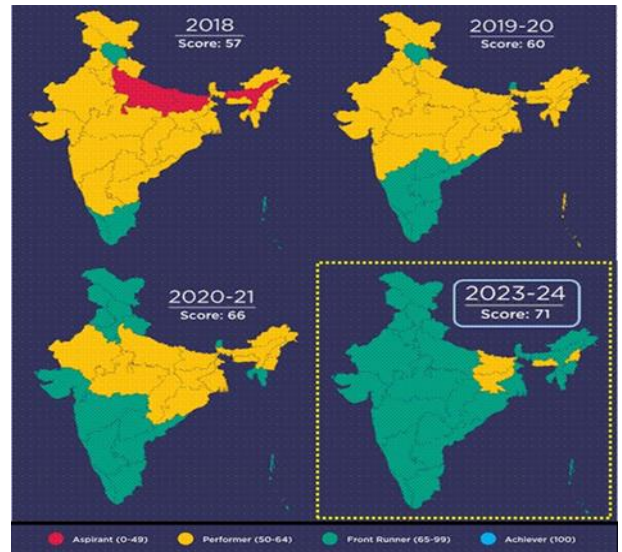
- 2024-25 के लिए बजटीय उर्वरक सब्सिडी 163,999.80 करोड़ रुपये है, जो 2023-24 में 189,487.44 करोड़ रुपये और 2022-23 में 251,339.36 करोड़ रुपये से कम है।
- वैश्विक बाजार में बदलाव के कारण आयातित यूरिया, डीएपी और एमओपी की कीमतों में हाल ही में काफी कमी आई है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स

संदर्भ: सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए भारत के प्रमुख उपकरण का चौथा संस्करण एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, आज नीति आयोग द्वारा जारी किया गया।

➤ समग्र स्कोर सुधार:

- 2018 में 57 से बढ़कर 2020-21 में 66 और 2023-24 में 71 हो गया।
- यह एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्रीय प्रगति को दर्शाता है, जो ठोस प्रयासों और प्रभावी नीति हस्तक्षेपों से प्रभावित है।



➤ 'फ्रंट रनर' श्रेणी में लक्ष्य:

- लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास), और 13 (जलवायु कार्रवाई) ने नवीनतम मूल्यांकन में 65-99 के बीच स्कोर प्राप्त किया है।
- लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) में 54 से 67 तक महत्वपूर्ण स्कोर वृद्धि देखी गई, जो पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में केंद्रित प्रयासों को दर्शाता है।
- लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) 60 से बढ़कर 72 हो गया, जो गरीबी उन्मूलन उपायों में प्रगति को दर्शाता है।

➤ क्षेत्रीय प्रगति:

- लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा), और 11 (स्थायी शहर और समुदाय) ने महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है।
- पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी सरकारी पहलों ने इन मील के पत्थरों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- डिजिटल बुनियादी ढाँचे और वित्तीय समावेशन में सुधार ने भी विकास परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

➤ सरकारी कार्यों की प्रगति:

- पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालयों और 2.23 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण।
- पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों का वितरण।
- जल जीवन मिशन के माध्यम से 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन का प्रावधान।

Face to Face Centres





13 July, 2024

- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा कवरेज।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को कवरेज।
- प्राथमिक चिकित्सा देखभाल और सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ प्रदान करने वाले 150,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना।
- पीएम-जन धन खातों के माध्यम से कुल ₹34 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)।
- कौशल भारत मिशन जैसी कौशल विकास पहल, 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर रही है।
- उद्यमशीलता की आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए पीएम मुद्रा योजना ने ₹22.5 लाख करोड़ की राशि के 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए।
- स्टार्ट अप इंडिया और स्टार्ट अप गारंटी योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप के लिए समर्थन।
- सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली की पहुँच का विस्तार।
- अक्षय ऊर्जा पर जोर, दशक भर में सौर ऊर्जा क्षमता को 2.82 गीगावाट से बढ़ाकर 73.32 गीगावाट करना।
- 2017 और 2023 के बीच स्थापित विद्युत क्षमता में लगभग 100 गीगावाट की वृद्धि, जिसमें से 80% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों के कारण है।
- डिजिटल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार, इंटरनेट डेटा लागत में 97% की कमी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

▶ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन:

- राज्य के स्कोर 57 से 79 के बीच हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर 65 से 77 के बीच हैं, जो पिछले आकलन की तुलना में बेहतर समग्र प्रदर्शन को दर्शाता है।
- 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 'फ्रंट रनर' का दर्जा हासिल किया (स्कोर 65 से 99 के बीच), जो पहले के 22 से अधिक है।
- दस नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 'फ्रंट रनर' श्रेणी में शामिल हुए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं।
- पिछले मूल्यांकन के बाद से असम, मणिपुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों द्वारा 8 अंकों तक उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।

▶ समग्र प्रगति:

- अंकों में 1 से 8 अंकों तक की वृद्धि देखी गई, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयासों का संकेत है।
- केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग इन प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है।
- गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर निरंतर ध्यान आगे की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

चालक दल स्वास्थ्य और प्रदर्शन अन्वेषण एनालॉग/क्यू

हेल्थ एंड परफॉरमेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग

(CHAPEA)

संदर्भ: 6 जुलाई को, चार स्वयंसेवी क्यू सदस्यों ने मंगल ग्रह पर जीवन का अनुकरण करने वाले एक साल के मिशन का समापन किया, जो लाल (मंगल) ग्रह पर व्याप्त स्थितियों को दोहराने के लिए डिज़ाइन किए गए आवास से निकलकर आया।

▶ मिशन प्रकार्य

- क्यू हेल्थ एंड परफॉरमेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग (CHAPEA) ह्यूस्टन, टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर में मंगल मिशन का अनुकरण करता है।
- इसमें तीन मिशनों की एक श्रृंखला शामिल है, जिनमें से पहला 25 जून, 2023 को शुरू हुआ।
- मिशन का आवास, मार्स ड्यून अल्फा, 1700 वर्ग फीट में विस्तृत है और मंगल ग्रह की सतह की स्थितियों की नकल करता है।

▶ आवास की विशेषताएँ

- मार्स ड्यून अल्फा में रहने के लिए क्वार्टर, एक व्यायाम क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, एक मनोरंजन क्षेत्र और एक फसल की खेती वाला खंड शामिल है।
- इसका बाहरी भाग लाल मिट्टी और चट्टानों के साथ मंगल के परिदृश्य की नकल करता है, जो संभावित रूप से 3D-मुद्रित आवास प्रयोगों के लिए काम आता है।
- आवास और हेंगर के बीच चालक दल का प्रवेश एक एयरलॉक के माध्यम से होता है।

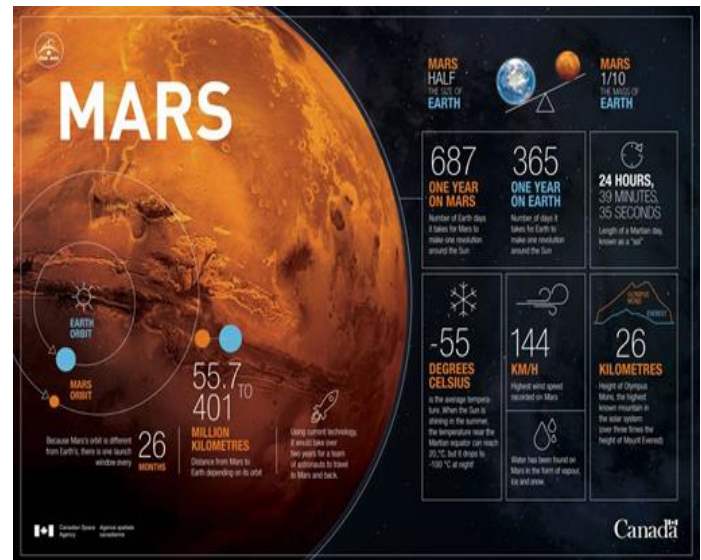
मिशन विवरण

▶ CHAPEA 1

- CHAPEA 1 25 जून, 2023 को शुरू हुआ और 6 जुलाई, 2024 को समाप्त हुआ, जो 378 दिनों तक चला।
- CHAPEA 1 के चालक दल के सदस्यों में केली हेस्टन (मिशन कमांडर), रॉस ब्रॉकवेल (स्ट्रक्चरल इंजीनियर), नाथन जोन्स (आपातकालीन चिकित्सा चिकित्सक) और एंका सेलारियू (सूक्ष्म जीवविज्ञानी) शामिल थे।
- CHAPEA 1 के लिए आवेदकों को 30-55 वर्ष की आयु के अमेरिकी स्थायी निवासी या नागरिक होने चाहिए, जिनके पास विमानन, STEM क्षेत्रों या चिकित्सा प्रमाण-पत्रों में विशिष्ट योग्यताएँ हों।

▶ भविष्य की संभावना:

- CHAPEA 2 वर्ष 2025 के लिए निर्धारित है, जिसके लिए 16 फरवरी से 2 अप्रैल, 2024 तक आवेदन स्वीकार किए जाएँगे।
- CHAPEA 3, श्रृंखला का अंतिम मिशन, 2026 के लिए योजनाबद्ध है।



Face to Face Centres



NEWS IN BETWEEN THE LINES

नाबाई



हाल ही में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) ने स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों (एग्री-श्योर) के लिए एक कृषि कोष की घोषणा की है, जिसमें 750 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि होगी, जिसका प्रबंधन इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नैबवेंचर द्वारा किया जाएगा।

नाबाई के बारे में:

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) भारत का शीर्ष विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1982 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।
- श्री बी. शिवरामन की अध्यक्षता वाली समिति ने इसकी अनुशंसा की थी और 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से इसे स्वीकृति दी गई थी।
- यह कृषि गतिविधियों को पुनर्वित्तपोषित करने, ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने, कृषि और ग्रामीण विकास संस्थानों को बढ़ावा देने और तकनीकी सहायता प्रदान करने सहित विभिन्न कार्य करता है।
- उल्लेखनीय पहलों में एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और वाटरशेड विकास परियोजनाएं शामिल हैं।
- यह वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षण सहित विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित होता है, जो पुनर्वित्त सहायता, जिला-स्तरीय ऋण योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण और सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है।

गिरनार वन्यजीव अभयारण्य



हाल ही में, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय (JAU) में उस समय अफरातफरी मच गई जब गिरनार वन्यजीव अभयारण्य से एक तेंदुआ कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (CAET) की प्रयोगशाला में घुस गया।

गिरनार वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

- गिरनार वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है।
- इसे 2008 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 2021 में आंगंतुकों के लिए सफारी राइड की शुरुआत की गई।
- अभयारण्य बड़ी गिरनार पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे पवित्र माना जाता है और यह हिंदुओं तथा जैनियों दोनों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है।
- यह वन्यजीव अभयारण्य, सवाना घास के मैदानों और विशिष्ट वन्यजीवों का एक असाधारण मिश्रण है। यह एशियाई शेरों का घर है जो पार्क के पहाड़ी और वन क्षेत्र में रहते हैं।
- वनस्पति:** अभयारण्य में विविध वनस्पतियाँ हैं, जिनमें शुष्क पर्णपाती वन, काटेदार झाड़ियाँ और घास के मैदान शामिल हैं।
- जीव-जंतु:** अभयारण्य विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का आवास है, जिनमें एशियाई शेर, चित्तीदार हिरण, तेंदुआ, भारतीय सुनहरे सियार, भालू, सांभर और चीतल शामिल हैं।

त्रिशूली नदी



हाल ही में, नेपाली सेना के जवानों ने चितवन में भूस्खलन के कारण दो बसों के त्रिशूली नदी में बह जाने के बाद बचाव अभियान चलाया, जिसमें सात भारतीय नागरिकों सहित कम से कम 63 लोग लापता हो गए।

त्रिशूली नदी के बारे में:

- मध्य नेपाल में स्थित त्रिशूली नदी नारायणी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो अंततः गंगा में मिल जाती है।
- "त्रिशूली" नाम भगवान शिव के त्रिशूल ("त्रिशूल") से लिया गया है, जो इसके पौराणिक महत्व को दर्शाता है।
- यह नेपाल-तिब्बत सीमा पर रसुवा किले के पास लंगटांग हिमाल क्षेत्र (हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा) से निकलती है, जो किरांग त्सांगपो और लेंडे खोला के संगम से प्रवाहित होती है।
- यह बेत्रावती (तीन प्रमुख नदियों, बेट्रान गंगा, रुद्र गंगा और त्रिशूल गंगा का मिलन स्थल) में भोटे कोशी नदी में मिल जाती है और आगे की ओर बहते हुए नारायणी नदी में मिल जाती है।
- ऊपरी त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना (यूटी-1 या परियोजना) नेपाल में ऊपरी त्रिशूली नदी पर 216 मेगावाट का ग्रीनफील्ड रन-ऑफ-रिवर जलविद्युत संयंत्र है। यह नदी व्हाइट-वाटर राफ्टिंग और कयाकिंग के लिए लोकप्रिय है, जो पर्यटकों और साहसिक उत्साही लोगों को आकर्षित करती है।

Face to Face Centres





13 July, 2024

<p>स्कवैलस हिमा</p> 	<p>हाल ही में, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल में शक्तिकुलंगरा मछली पकड़ने के बंदरगाह से गहरे पानी में रहने वाली डॉगफ़िश शार्क की एक नई प्रजाति, स्कवैलस हिमा की खोज की है।</p> <p>स्कवैलस हिमा के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> स्कवैलस हिमा स्कवैलिडे परिवार के भीतर स्कवैलस जीनस से संबंधित है, जिसे आमतौर पर स्पेरडॉग के रूप में जाना जाता है, जिसकी विशेषता चिकनी पृष्ठीय पंख रीढ़ है। यह हिंद महासागर की गहराई में, विशेष रूप से सेशेल्स और मॉरीशस के आसपास रहती है। इसकी विशेषता इसका छोटा आकार है, जो आमतौर पर लगभग 50 सेमी लंबा होता है और बड़ी आँखें और हल्के रंग का शरीर जैसी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं। स्कवैलस और सेंट्रोफ़ोरस जेनेरा की प्रजातियाँ, जिनमें स्कवैलस हिमा भी शामिल है, लिबर ऑयल के लिए इनका शिकार किया जाता है, जिसका दवा उद्योग में अत्यधिक महत्व है।
<p>सुर्खियों में स्थल</p> <p>लिथुआनिया</p>	<p>लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने कल 12 जुलाई, 2024 को दूसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली।</p> <p>लिथुआनिया (राजधानी: विनियस)</p> <p>स्थान: लिथुआनिया, जिसे आधिकारिक तौर पर लिथुआनिया गणराज्य के रूप में जाना जाता है, यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है।</p> <p>सीमाएँ: लिथुआनिया की सीमा बेलारूस (पूर्व और दक्षिण), बाल्टिक सागर (पश्चिम), लातविया (उत्तर), पोलैंड (दक्षिण) और रूस (दक्षिण-पश्चिम) से लगती है।</p> <p>भौतिक विशेषताएँ:</p> <ul style="list-style-type: none"> लिथुआनिया का सबसे ऊँचा स्थान औकस्टोजस हिल है, जिसे जुओज़ापिन हिल के नाम से भी जाना जाता है। लिथुआनिया की प्रमुख नदियों में नेमुनास (नेमन), नेरिस, स्वेन्टोजी और वेंटा नदियाँ शामिल हैं। डूकशिया झील देश की सबसे बड़ी झील है। लिथुआनिया में मिट्टी, चूना पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट सहित विभिन्न खनिजों के छोटे भंडार हैं। स्वतंत्रता: लिथुआनिया ने 1990 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की और 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। 

POINTS TO PONDER

- किस संगठन ने हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत निजी क्षेत्र के लिए सात नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? – **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)**
- हाल ही में, किस सैन्य दल ने अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है? – **भारतीय वायु सेना (IAF) दल**
- तिरुवनंतपुरम में स्थित विज्ञानजाम बंदरगाह, भारत का पहला डीपवाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। सार्वजनिक निजी भागीदारी घटक के साथ, किस मॉडल के तहत बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? – **लैंडलॉर्ड मॉडल**
- भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) की किस प्रणाली के लिए इन्फ्रारेड स्टार कैटलॉग बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स टूल विकसित किया है? – **अनुकूली प्रकाशिकी प्रणाली**
- IUCN रेड लिस्ट विलुप्त होने के जोखिम वाली प्रजातियों को नौ श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। वर्तमान में सूची में लगभग कितनी प्रजातियाँ शामिल हैं, और उनमें से कितनी विलुप्त होने के खतरे में हैं? – **163,000 प्रजातियाँ; 45,000 खतरे में**

Face to Face Centres

